



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/चैत्र 6, 1939

No. 112]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसदीय अधिनियम के अंतर्गत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

राँची, 26 मार्च, 2017

सं. झा.के.वि./विनियम/04/2010.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

ओ ए - 2

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

पढ़ाई एवं परीक्षा का माध्यम

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अंतर्गत परिनियम के साथ पठित]

1. जब तक विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय नहीं किया जाता विश्वविद्यालय में शोध व अध्ययन के लिए पढ़ाई एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

ओ ए - 5

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विभाग/केन्द्र अध्यक्ष एवं विभाग/केन्द्र अध्यक्ष की शक्ति एवं कार्य

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 परिनियम 15 के साथ पठित]

1. नियुक्ति

- (i) ऐसे विभाग/केन्द्र जहाँ एक से अधिक प्रोफेसर हैं, विभाग/केन्द्र अध्यक्ष की नियुक्ति प्रोफेसरों में से कुलपति की अनुशंसा पर शासी परिषद द्वारा की जाएगी।
- (ii) ऐसे विभाग/केन्द्र जहाँ केवल एक ही प्रोफेसर है, शासी परिषद के पास विकल्प होगा कि, कुलपति की अनुशंसा पर, प्रोफेसर या सह प्रोफेसर को विभाग/केन्द्र अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यह भी कि प्रोफेसर या सह प्रोफेसर को विकल्प होगा कि वह विभाग/केन्द्र अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति को अस्वीकार कर सकते/सकती हैं।
- (iii) विभाग/केन्द्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा एवं वह पुनःनियुक्ति के लिए योग्य होंगे/होंगी, परंतु लगातार तीसरी अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऊपर किसी बात का होते हुए शिक्षक सेवानिवृत्ति की आयु को पहुंचने पर अध्यक्ष नहीं रहेंगे/रहेंगी।

(iv) विभाग/केन्द्र अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे सकते/सकती हैं।

2. विभाग/केन्द्र अध्यक्ष का निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य होंगे :

(i) विभाग/केन्द्र अध्यक्ष डीन के सामान्य देखरेख में विभाग/केन्द्र की बैठक बुलाएंगे एवं अध्यक्षता करेंगे :

- क) विभाग/केन्द्र ने शिक्षण व शोध कार्य का आयोजन करेंगे/करेंगी;
- ख) विभाग/केन्द्र द्वारा शिक्षक कार्य के आवंटन के अनुसार समय सारणी बनाएंगे/बनाएंगी;
- ग) शिक्षकों के माध्यम से कक्षा तथा प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखेंगे/रखेंगी;
- घ) विभाग/केन्द्र के सुचारु कार्य के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, विभाग/केन्द्र के शिक्षकों का काम देंगे या विभाग/केन्द्र में शिक्षक के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का काम देंगे/देंगी; और
- च) डीन, संबंधित स्कूल बोर्ड, अकादमिक परिषद, शासी परिषद एवं कुलपति द्वारा दिए गए अन्य काम भी करेंगे/करेंगी।

3. निष्कासन*

विभाग/केन्द्र अध्यक्ष को कार्यालय से निष्कासित किया जा सकता है:

- क) यदि वह लम्बे समय से वह बीमार रह रहे हों जिससे विभाग/केन्द्र कार्यालय का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
- ख) यदि वह विभाग/केन्द्र एवं विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध काम करते पाए जाते/जाती हैं।

कुलपति इस विषय पर डीन की एक समिति का गठन करेंगे जिनकी सिफारिशों को शासी परिषद के समक्ष रखा जाएगा तथा इस विषय पर उनका संकल्प अंतिम होगा।

निष्कासन की स्थिति में शासी परिषद के कुल सदस्यों में से कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिनमें से कम से कम तीन चौथाई सदस्य निष्कासन के संकल्प के पक्ष में हों। अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं।

*सक्षम बनाने वाले खंड परिनियम में वांछनीय है।

ओ ई - 1

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश, विनियम एवं नियम में नहीं आए विषय पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(xxv)]

कोई विशेष विषय या मामला जो झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश, विनियम एवं नियम में नहीं आया है, समय-समय पर लागू भारत सरकार के नियम व कायदा के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

डीन समिति

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(b) के अंतर्गत]

विश्वविद्यालय डीन की एक समिति का गठन करेगा जो डीन समिति के नाम से जाना जाएगा।

गठन 1. डीन समिति में निम्नलिखित लोग होंगे :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. कुलपति | — अध्यक्ष |
| 2. सभी स्कूलों के डीन | — सदस्य |
| 3. परीक्षा नियंत्रक | — सदस्य |
| 4. वित्त अधिकारी | — सदस्य |
| 5. कुलसचिव | — सदस्य सचिव |

- कार्य**
2. इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :
 - क. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर विचार करना;
 - ख. परीक्षा कराने, परीक्षाफल का मापदंड इत्यादि संबंधी मामलों पर यथाआवश्यक विचार करना;
 - ग. स्कूलों व विभागों के कार्य संबंधी सामान्य प्रशासनिक मामलों पर विचार करना; और
 - घ. शासी परिषद द्वारा दिए गए अन्य मामलों या कुलपति द्वारा भेजे गए मामलों पर विचार करना।

- कोरम**
3. डीन समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।
 4. समिति का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।
 5. बैठक करने संबंधी नियम विनियम में दिया जाएगा।

नोट : इन नियमों पर किसी प्रकार का संदेह या विरोधाभास की स्थिति में मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिर्देश मान्य होंगे।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(व) के अंतर्गत]

दिनांक 21.10.2009 की अधिसूचना संख्या एफ.1-6/2009(सीपीपी ।।) द्वारा अधिसूचित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधित "उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण (2009)" पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम के अंतर्गत रैगिंग प्रतिबंधित एवं दंडनीय है।

कार्य व नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय के विनियम के अंतर्गत निर्धारित होंगे।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

परीक्षा/उपाधि की मान्यता के लिए समानता समिति

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(0) के अंतर्गत]

- संरचना**
1. एक समानता समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. कुलपति या उनके नामिति — अध्यक्ष
2. सभी स्कूलों के डीन — सदस्य
3. अकादमिक परिषद के सदस्यों में से एक व्यक्ति
जो अकादमिक परिषद द्वारा तीन वर्षों के लिए
नामित किया जाएगा — सदस्य
4. कुलसचिव — सदस्य
5. परीक्षा नियंत्रक — सचिव

- कार्य**
2. इस समिति का कार्य होगा :

- क) समय-समय पर समिति को भेजे गए विदेशी विश्वविद्यालयों सहित परीक्षा/उपाधियों की समानता की जाँच करना एवं अकादमिक परिषद को अपनी संस्तुति देना।
- ख) कारण एवं अवधि बताते हुए जो समिति उचित समझे किसी परीक्षा/उपाधि को रोकने, स्थगित करने या निरस्त/मान्यता करने संबंधी मामलों की जाँच करना एवं अकादमिक परिषद को अपनी संस्तुति देना।
- ग) जहाँ भी आवश्यक हो समिति किसी विषय विशेषज्ञ को अपने काम में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

- कार्य नियम**
3. समिति, अकादमिक परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए, अपना कार्य करने का नियम एवं दिशा-निर्देश बनाएगी।
अकादमिक परिषद इस मामले में अपनी किसी भी शक्ति को समानता समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

खेलकूद समिति

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(व) के अंतर्गत]

संरचना

1. एक खेलकूद समिति होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- (i) डीन, छात्र कल्याण, अध्यक्ष होंगे;
- (ii) कुलपति द्वारा नामित दो प्रख्यात खिलाड़ी;
- (iii) एक उत्कृष्ट महिला/पुरुष खिलाड़ी जो अध्यनरत विद्यार्थियों में से होंगे एवं अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे; एवं
- (iv) निदेशक, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

कार्य

2. समिति:

- (i) विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए उपाय करेगी;
 - (ii) विश्वविद्यालय के खेलकूद का प्रबंध एवं निगरानी करेगी एवं इस विषय पर विनियम बनाएगी;
 - (iii) खेलकूद के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रस्ताव देगी;
 - (iv) विश्वविद्यालय के खेल—मैदान, जिम, स्वीमिंग पुल तथा अन्य खेलकूद सुविधाओं का रखरखाव करेगी;
 - (v) प्रतियोगिताएं, टूर्नामेन्ट, एथलेटिक मीट इत्यादि आयोजित करेगी;
 - (vi) खेलकूद कोटा, यदि कोई हो, के अंतर्गत प्रवेश के लिए कुलपति को उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुशंसा करेगी;
 - (vii) प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधा/छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, के लिए कुलपति उत्कृष्ट खिलाड़ी का नाम की अनुशंसा करेगी; एवं
 - (viii) शासी परिषद, अकादमिक परिषद/कुलपति द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य काम को पूरा करेगी।
3. निदेशक, शारीरिक शिक्षा आवंटित धन को डीन, छात्र कल्याण की देखरेख में परिचालित करेंगे।

बैठक

4. डीन छात्र कल्याण की देखरेख में समिति दो माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

कोरम

5. समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों में से एक तिहाई कोरम का निर्माण करेंगे।
6. ऐसी स्थिति/मामले जो इन नियमों में नहीं हैं, वहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिर्देश का पालन किया जाएगा।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

भूतपूर्व छात्र संघ

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(व) के अंतर्गत]

1. विश्वविद्यालय का एक भूतपूर्व छात्र संघ होगा।
2. संघ का उद्देश्य होगा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना, विश्वविद्यालय के स्नातकों के बीच संपर्क एवं एकजुटता बनाना एवं विश्वविद्यालय के विकास के लिए धन इकट्ठा करना।
3. संघ की सदस्यता डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट धारकों सहित विश्वविद्यालय के सभी उपाधि धारकों के लिए खुली होगी।
4. संघ की सदस्यता शुल्क 500/- रु प्रति वर्ष होगा तथा 10,000/-रु जीवन भर के लिए या विश्वविद्यालय के शासी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क।
5. भूतपूर्व छात्र संघ के लिए प्रवेश शुल्क भी होगा जो 100/- रु होगा जो विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय लिया जाएगा।
6. सदस्यता के लिए आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा।
7. संघ की कार्यकारी समिति में होंगे
 - क) अध्यक्ष;
 - ख) उपाध्यक्ष;
 - ग) महासचिव;

- घ) संयुक्त सचिव; तथा
च) 10 अन्य सदस्य।
8. कुलपति पदेन संरक्षक होंगे। संघ के अन्य सभी पदाधिकारीगण तथा सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाएंगे।
 9. संघ का कोई भी सदस्य वोट देने का हकदार या चुनाव लड़ने का हकदार तभी होगा जब वह चुनाव तिथि से एक साल पहले से सदस्य है एवं कम से कम पांच सालों से विश्वविद्यालय उपाधि का धारक है।
 10. यह भी कि सदस्यता का एक साल पूरा होने संबंधी शर्त पहले चुनाव के मामले में लागू नहीं होगा।
 11. संघ का धन विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा संचालित होगा जो इस कार्य के लिए एक अलग खाता रखेंगे।
 12. संघ का चुनाव तथा इसकी बैठकें विनियम में निर्धारित तरीकों के अनुसार की जाएंगी।
 13. अध्यादेश के किसी भी खंड पर काम करने में कठिनाई होने की स्थिति में मामले को कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय उस मामले में अंतिम होगा।
 14. ऐसी स्थिति/मामले जो इन नियमों में नहीं आते, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विनर्देश का पालन किया जाएगा।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

कर्मचारी व विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति

पर अध्यादेश

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(द) के अंतर्गत]

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक पद्धति बनाई जाएगी।

अभिप्राय जब तक कि उल्लिखित न हो:

विद्यार्थी से अभिप्राय है ऐसे सभी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के किसी स्कूल/केन्द्र/विभाग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध किए जा रहे परिसर में पंजीकृत हों।

कर्मचारी से अभिप्राय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जिसमें शिक्षक व अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।

सामान्य सिद्धांत शिकायत समिति निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत का अनुसरण करेगी:

1. परिसर समुदाय को शिकायत निवारण पद्धति से पूरी तरह अवगत कराएगी;
2. विद्यार्थी/कर्मचारी के प्रत्येक शिकायत को पंजीकृत किया जाएगा एवं पावती दी जाएगी;
3. यदि पंद्रह दिनों के भीतर निर्णय संभव न हो तो, आवेदक को पावती भेजी जाएगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि वह कब तक अंतिम निर्णय की अपेक्षा कर सकता है;
4. सामान्य नियम होगा कि कोई भी शिकायत तीन माह के सीमा के बाहर लंबित न हो;
5. कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति तथा शिकायतों के दूर करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नीयत समय पर सप्ताह कम से कम एक बार शिकायतों को सुनने के लिए उलब्ध रहना होगा; तथा
6. वह तीन माह से अधिक लंबित शिकायतों पर निर्णय लेगा/लेगी। असंतुष्ट व्यक्ति जो अधीनस्थ/संलग्न संरचना के निवारण से संतुष्ट नहीं है, कुलपति के पास निर्णय के लिए जा सकते हैं।

संरचना एवं कार्य **I. विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति**

अध्यक्ष – प्रति कुलपति या कुलपति द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति

सदस्य:

विद्यार्थी परिषद के तीन प्रतिनिधि

कुलपति के तीन नामिति

डीन, छात्र कल्याण, सदस्य सचिव

संबंधित स्कूल के डीन (विशेष आमंत्रित)

शक्ति व कार्य:

- (i) विद्यार्थियों के संबंध में व्यक्तिगत या समूह के रूप में प्रभावित करने वाले मामलों पर लिखित व हस्ताक्षरित शिकायत एवं आवेदन पर विचार करना;

- (ii) शिकायतों की जाँच करना, तथा संबंधित प्राधिकारों — अकादमिक परिषद एवं शासी परिषद को शिकायत दूर करने या उचित कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा व रिपोर्ट देना; और
- (iii) दस्तावेज में दिए गए आरोप आधारहीन पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना।

II. शिक्षक शिकायत निवारण समिति

शासी परिषद द्वारा गठित एक समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :

कुलपति या उनका प्रतिनिधि — अध्यक्ष।

शिक्षक समुदाय से पाँच प्रतिनिधि जो लिंग, अल्पसंख्यक, अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

कुलपति के नामित समिति के सचिव होंगे।

शक्ति व कार्य:

- (i) शिक्षकों के संबंध में व्यक्तिगत या समूह के रूप में प्रभावित करने वाले मामलों पर लिखित व हस्ताक्षरित शिकायत एवं आवेदन पर विचार करना;
- (ii) शिकायतों की जाँच करना, तथा संबंधित प्राधिकारों — अकादमिक परिषद एवं शासी परिषद को शिकायत दूर करने या उचित कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा व रिपोर्ट देना; और
- (iii) दस्तावेज में दिए गए आरोप आधारहीन पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना।

III. शिक्षकेतर शिकायत निवारण समिति

अध्यक्ष — कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे।

शिक्षकेतर समुदाय से पाँच प्रतिनिधि जो लिंग, अल्पसंख्यक, अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

कुलसचिव या उनके नामित समिति के सदस्य सचिव होंगे।

शक्ति व कार्य:

- (i) कर्मचारियों (शिक्षकेतर) के संबंध में व्यक्तिगत या समूह के रूप में प्रभावित करने वाले मामलों पर लिखित व हस्ताक्षरित शिकायत एवं आवेदन पर विचार करना;
- (ii) शिकायतों की जाँच करना, तथा संबंधित प्राधिकारों — अकादमिक परिषद एवं शासी परिषद को शिकायत दूर करने या उचित कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा व रिपोर्ट देना; और
- (iii) दस्तावेज में दिए गए आरोप आधारहीन पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना।

नोट: इन नियमों पर कोई संदेह या विरोधाभास होने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिर्देश मान्य होगा।

प्रो. आर. के. डे., कुल सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./484/16]

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(A Central University established by an act of Parliament of India in 2009)

NOTIFICATION

Ranchi, the 26th March, 2017

No. CUJ/Regulation/04/2010.—The following is published for general information:—

OA - 2

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

ORDINANCE ON

THE MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATION

[Under Section 28 of the Central Universities Act, 2009 read with Statute]

1. English shall be the medium of instruction and examination in the research and study programmes of the University unless otherwise decided by the University.

OA-5

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND**ORDINANCE ON****HEADS OF DEPARTMENTS/CENTRES AND POWERS & FUNCTIONS OF HEADS OF DEPARTMENTS/CENTRES***[Under Section 28 of the Central Universities Act, 2009 read with Statutes 15]***1. Appointment**

- (i) In the case of Department/Centres which have more than one Professor, the Head of the Department/Centre shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor from among the Professors.
- (ii) In the case of Department/Centres where there is only one Professor, the Executive Council shall have the option to appoint, on the recommendation of the Vice-Chancellor, either the Professor or an Associate Professor as the Head of the Department.

Provided that it shall be open to a Professor or Associate Professor to decline the offer or appointment as the Head of the Department/Centre.

- (iii) A person appointed as the Head of the Department/Centre shall hold office as such for a period of three years and shall be eligible for re-appointment, but shall not be considered for third consecutive term. Notwithstanding anything contained above a teacher shall cease to be Head on attaining the age of superannuation.
- (iv) A Head of a Department/Centre may resign her/his office at any time during her/his tenure of office.

2. The Head of Department/Centre shall have the following powers and functions

- (i) The Head of Department/Centre of studies shall convene and preside over meetings of the Department/Centre, and shall under the general supervision of the Dean:
 - a) organize the teaching and research work in the Department/Centre;
 - b) frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department /Centre;
 - c) maintain discipline in the class room and laboratories through teachers;
 - d) assign to the teachers in the Department/Centre such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department/Centre or and assign work to and exercise control over the non-teaching staff in the Department / Centre and
 - e) perform such other functions as may be assigned to him by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council, the Executive Council and the Vice-Chancellor.

3. Removal*

A Head of Department/Centre may be removed from office:

- a) if she/he has been found to be maintaining indifferent health for long period(s) of time so as to adversely affect the working of the office of the Department/Centre,
- b) if she/he has been found to work against the interest of the Department/Centre and the University.

The Vice-Chancellor shall constitute a Committee of Deans on the matter and shall place the recommendation of the Committee to the Executive Council, which resolution shall be final.

In the case of removal, at least three fourth of the total members of the Executive Council must be present, of which at least three fourth should be in favour of the resolution for removal. The Chairman may exercise a casting role.

*Enabling Clause desirable in Statutes

OE-1

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND**ORDINANCE ON****THE MATTERS WHICH ARE NOT COVERED BY ORDINANCE, REGULATIONS AND RULES OF THE UNIVERSITY***[Under Section 6 (I) (xxv) and 28 of the Central University Act, 2009]*

A particular subject or an individual case which is not covered by the Ordinance, Regulations, and Rules of the University shall be dealt with in accordance with the rules and norms of the Government of India, as applicable from time to time.

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND**ORDINANCE ON****DEANS COMMITTEE***[Under Section 28(1)(i) and (o) of the Central University Act 2009]*

1. The University shall constitute a Committee of Deans of the University to be known as the Deans' Committee.
- Constitution**
2. The Deans' Committee shall comprise the following:
 - i. The Vice-Chancellor - Chairperson (Ex-Officio)
 - ii. All Deans of Schools - Members (Ex-Officio)
 - iii. Controller of Exams - Members
 - iv. Finance Officer - Member
 - v. Registrar - Member Secretary
- Function**
3. The functions of this Committee will be as follows :
 - a. To recommend deputation of teachers for international Conferences;
 - b. To consider such matters as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of results, etc;
 - c. To consider general administrative matters relating to functioning of Schools and Departments; and
 - d. To consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to by the Vice-Chancellor.
 4. The meetings of the Deans' Committee shall be convened by the Chairperson.
- Quorum**
5. The quorum of the Committee shall be 1/3rd of the total number.
 6. The rules of conduct of meetings shall be as may be prescribed by Regulations in this regard.

Note: In case of any doubt or contradiction of these rules, Instructions of Govt. of India. Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission, shall prevail

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND**ORDINANCE ON****CURBING THE MENACE OF RAGGING***[Under Section 28 (n) of the Central University Act, 2009]*

Ragging is prohibited and punishable under the UGC Regulations on "Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (2009)" notified vide No. F.1-6/2009(CPP-II) dated 21.10.2009 and as amended by the UGC from time to time.

The functioning and terms and conditions shall be specified under the Regulations of the University.

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
ORDINANCE ON
EQUIVALECE COMMITTEE FOR RECOGNITION OF
EXAMINATIONS/DEGREES

[Under Section 28(1)(o) of the Central University Act 2009]

Composition

1. There shall an Equivalence Committee consisting of the following members:

- | | | | |
|-------|---|---|-----------|
| (i) | Vice Chancellor or his nominee | - | Chairman |
| (ii) | Deans of the Schools | - | Members |
| (iii) | One person nominated by the Academic Council from amongst its members for a period of three years | - | Member |
| (iv) | Registrar | - | Member |
| (v) | Controller of Examination | - | Secretary |

Function

2. The functions of this Committee shall be :

- (i) To examine and recommend to the Academic Council equivalent of such examinations/degrees as may be referred to it from time to time including those of foreign Universities.
- (ii) To examine and recommend to the Academic Council the withholding, suspension or cancellation/recognition to any examination/degree for such reasons and such time it may deem fit.
- (iii) The Committee may invite a domain expert, wherever necessary, to assist it in its functioning.

Rules of Business

3. The Committee shall frame the rules of business and lay down guidelines for consideration and approval of the Academic Council. The Academic Council may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
ORDINANCE ON
GAMES AND SPORTS COMMITTEE

[Under Section 28(1)(o) of the Central University Act 2009]

Composition

1. There shall be a Games and Sports Committee consisting of the following members namely:

- (i) The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairperson;
- (ii) Two prominent sportspersons to be nominated by the Vice Chancellor;
- (iii) One Outstanding Sportsman/Sportswoman from among the students on rolls, nominated by the Chairman for a period of one year; and
- (iv) The Director of Physical Education, who shall be the Ex-Officio Member-Secretary of the Games and Sports Committee.

Function

2. The Committee shall:

- (i) take measures to attract the sports talent available in the University;
- (ii) make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;
- (iii) propose the budgetary requirements for games and sports;
- (iv) maintain the play-grounds, gymnasias, swimming pools and other sports facilities of the University;
- (v) hold/organise contests, competitions, tournaments, athletic meets etc.;

- (vi) recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players/ sportspersons to be nominated for admission under sports quota, if any;
- (vii) recommend to the Vice Chancellor names of the Outstanding player/Sportspersons for training/coaching facilities/stipend, if any; and
- (viii) perform such other functions, as may be assigned to it by the Executive Council/ Academic Council/ Vice Chancellor from time to time.
3. The Director, Physical Education will operate allotted fund under the supervision of the Dean of Students' Welfare.
- Meeting** 4. The Committee shall hold its meetings at least once in two months under the supervision of the Dean Students' Welfare.
- Quorum** 5. One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.
6. In such situation/cases not covered in these rules, instructions of Government of India, Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission, shall be followed.

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

ORDINANCE ON

THE ALUMNI ASSOCIATION

[Under Section 35 (2) of the Central Universities Act 2009]

1. There shall be an Alumni Association of the University.
2. The objective of the Association shall be to promote the objectives of the University, to maintain contacts and solidarity among the graduates of the University, and to raise funds for the development of the University.
3. The membership of the Association shall be open to all degree holders of the University, including the holders of diplomas and certificates.
4. The membership fee for the Association, shall be Rs. 500/= per year and Rs. 10,000/= for life or as decided by the Executive Council of the University from time to time.
5. There shall also be an Alumni Association Admission fee of Rs 100/- which shall be collected at the time of admission of students in the university.
6. The application for membership shall be in a form prescribed by the University.
7. The Executive Committee of the Association shall consist of the
 - (a) President;
 - (b) Vice President;
 - (c) General Secretary;
 - (d) Joint Secretary; and
 - (e) 10 other Members.
8. The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Patron. All other office -bearers and members of the Association shall be elected for a term of three years.
9. No member of the Association shall be entitled to vote or stand for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a degree holder of the University of at least five years' standing.
10. Provided that the condition relating to the completion of one year membership shall not apply in case of the first election.
11. The funds of the Association shall be managed by the Finance Officer of the University who will maintain a separate Account for the purpose.
12. The elections of the Association and all its meetings shall be conducted in the manner to be prescribed by Regulations.
13. In case of any difficulty in operating any clause of the Ordinance the matter shall be referred to the Vice-Chancellor whose decision thereon shall be final.

14. In such situation/cases not covered in these rules, instructions of Government of India, Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission, shall be followed.

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

ORDINANCE ON

EMPLOYEES AND STUDENTS' GRIEVANCES REDRESSAL COMMITTEE

[Under Section 28(n) of the Central University Act, 2009]

There shall be constituted a Mechanism for the redressal of the grievances of Employees and Students of the University.

Meaning

Unless otherwise mentioned:

Student means all students who are registered for a Programme of study in any School/Centre/Department College or Campus maintained by the University.

Employee means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University.

General Principles

The Grievances Committee shall observe the following general principles:

1. The Campus Community should be made fully aware of the grievance redressal Mechanism;
2. Every grievance from the student/ staff should be registered and acknowledged;
3. If a final decision is not possible within a fortnight, an acknowledgement should be sent to the applicant along with an indication as to when he/she can expect a final reply;
4. As a matter of general rule no grievances should remain pending beyond the limit of three months;
5. The officer nominated by the Vice-Chancellor and the person responsible for addressing grievances should make himself/herself freely available to hear the grievances personally, at least once a week at fixed timings; and
6. He/she will take decisions on grievances which are pending for more than three months. Aggrieved parties who are not satisfied with redressal in subordinate/attached formation can approach the Vice-Chancellor for a decision.

I. STUDENTS GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE

Constitution & Function

Chairman – The Pro Vice-Chancellor or such other person to be nominated by the Vice-Chancellor.

Members:

3 Representative of Students' Council.

3 Nominees of the Vice-Chancellor.

Dean of Students' welfare, Member-Secretary.

Dean of the School concerned (special invitee)

POWERS AND FUNCTIONS

- (i) to entertain written and signed complaints and petitions of student in respect of matters directly affecting them individually or as a group;
- (ii) to enquire into the grievances, and make recommendations and report to the concerned authorities – Academic Council and Executive Council for redressal or suitable action; and
- (iii) to recommend appropriate action against complainant, if allegations made in the documents are found to be baseless.

II. TEACHERS' GRIEVANCES COMMITTEE

There shall be constituted a Committee by the Executive Council consisting of the following:

Vice-Chancellor or his/ her representative Chairman.

Five representatives from the teacher community representing gender, minority, SC,ST,OBC

Vice-Chancellor's nominee shall be the Secretary to the Committee.

POWERS AND FUNCTIONS

- (i) to entertain written and signed complaints and petitions of teachers in respect of matters directly affecting them individually or as group;

- (ii) to enquire into the grievances, and make recommendations and report to the concerned authorities – Academic Council and Executive Council for redressal or suitable action; and
- (iii) to recommend appropriate action against complainant, if allegations made in the documents are found to be baseless.

III. NON-TEACHING STAFF GRIEVANCES COMMITTEE

The Chairman- to be nominated by the Vice-Chancellor.

Five representatives from the non-teaching community representing gender, minority, SC,ST,OBC

The Registrar or his nominee shall be the Member-Secretary of the Committee.

POWERS AND FUNCTIONS

- (i) to accept and consider written and signed complaints and petitions of staff (Non-teaching) in respect of matters directly affecting them individually or as group;
- (ii) to enquire into the grievances, and make recommendations and report to the concerned authorities – Academic Council and Executive Council for redressal or suitable action; and
- (iii) to recommend appropriate action against complainants, if allegations made in the documents are found to be baseless.

Note: In case of any doubt or contradiction of these rules, Instructions of Govt. of India. Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission, shall prevail

Prof. R.K. DEY, Registrar

[ADVT. III/4/Exty./484/16]